[श्री हरिकेश बहादुर]

महीने के अन्दर सभी बातें जोकि एग्रीमेन्ट में आई हुई हैं वह मान ली जायेंगी तो उन बातों को 31 मार्च 1978 तक मान लेना था। उन बातों को एम्प्लीमेन्ट क्यों नहीं किया गया इस बात की जानकारी माननीय मन्त्री महोदय हम लोगों को दें। अभी जो उन्होंने बताया है उस में हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। अगर यूनियन की बातों की इस प्रकार से उपेक्षा की जायेगी, अगर एग्रीमेन्ट किया जायेगा और फिर तोड़ा जायगा तो धीरे धीरे लोगों का विश्वास ही इस प्रकार के एग्रीमेन्ट से टूट जायेगा। विश्वविद्यालय की नौकरशाही ने जो रिपोर्ट मंत्री जी को दी है वह तो उन्होंने हमें बताई है लेकिन कर्मचारियों की जो ग्रीवांसेज हैं उनको भी सुनने की कोशिश होनी चाहिये। अगर कर्मचारियों की बात नहीं सुनेंगे तो कोई भी न्यायोचित समझौता नहीं हो सकता है। इसलिए हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं क्या उनके पास ऐसी कोई योजना है जिसके आधार पर वे कर्मचारियों तथा विश्वविद्यालय मैनेजमेन्ट के भी कुछ वरिष्ठ लोगों को बुलाकर मीटिंग करें और उसमें कुछ एम पीज भी बुलाये जाये जैसे कि श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी हैं जिन्होंने आई आई टी दिल्ली का जब सवाल उठा था तो उसका प्रश्न यहां पर उठाया था और प्रधान मंत्री जी के हस्तक्षेप से उस मामले का निपटारा हो गया था। क्या इस प्रकार की कोई बैठक मंत्री जी बुलायेंगे जिसमें कुछ संसत्सदस्य भी हों जोकि वारदातों से वाकिफ हों जैसे कि स्वामी जी हैं और दूसरे लोग हैं या लोकल एम पीज हैं, उनको बुलाकर बात करेंगे जिससे कि जल्दी से जल्दी समझौता हो जाये? मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे कर्मचारियों की बातों की उपेक्षा न करें बल्कि उनकी ग्रीवांसेज पर पूरा ध्यान देने की कृपा करें।

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: I have already explained the reasons for the delay. The steps have been taken. But because it involves many people and also many institutions and colleges under the University, the thing could not be expedited. The University alone cannot be held responsible. However, the University has given fresh offers in the letter which I have already mentioned and the *karamchari* Union can take steps. The parallel of IIT cannot apply here for the reason that IIT is only one institution whereas the University has got a large number of colleges under it. It is a much larger body. So, that is creating some difficulty.

It is not a fact that I am sitting idle. As soon as Mr. S. M. Banerjee, former Member of Parliament, rang me up last night, I gave him time and I discussed the matter with him this morning. Unless people approach me, I cannot intervene in a matter which comes within the purview of an autonomous institution. I rang up the Vice-Chancellor; he was not available. Certainly, if I am able to solve the problem, I shall certainly do it.

SHRI HARIKESH BAHADUR: I asked a very specific question as to whether he is going to invite the management and, at the same time, the *karmachari* union and have a meeting under his chairmanship so that the crisis can be solved.

MR. SPEAKER: He has replied that he cannot do it on his own; somebody has to initiate it.

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

NINETY-SECOND AND NINETY-FIFTH REPORT

SHRI P. V. NARASIMHA RAO (Hanamkonda): I beg to present the following Reports of the Public Accounts Committee:—

(1) Ninety-second Report on action taken by Government on the recommendations contained in the Twenty-first Report relating to Ministry of Home Affairs.

(2) Ninety-fifth Report on action taken by Government on the recommendations contained in the First Report relating to Ministry of Defence.

COMMITTEE ON PETITIONS

SIXTH REPORT

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : वाचस्पति महोदय, आप की अनुमति से मैं छठी लोक सभा की याचिका समिति का प्रतिवेदन षष्ठ सदन की सेवा में प्रस्तुत करता हूं।